शाह मनसुखलाल छगनलाल (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि

बनाम

गोहिल अमरसिंह गोविंदभाई (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि

5 दिसम्बर 2006

(न्यायमूर्ति डॉ अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया)

सिविल प्रक्रिया संहिता - 1908 धारा 100 द्वितीय अपील, जब कानून का सारगर्भित प्रश्न तैयार नहीं किया गया तो उसे बनाए रखने योग्य - माना गया: बनाए रखने योग्य नहीं।

कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर शब्द और वाक्यांश अभिव्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 (5) के संदर्भ में अर्थ।

वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के संदर्भ में दायर दूसरी अपील को अनुमति देना उचित था।

अपील का निपटारा करते हुए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह नहीं पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या प्रश्न पर दूसरी अपील सुनी गई थी, यदि कोई हो। इस प्रकार तैयार किया गया। ऐसा होने पर निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल (2000) 1 एससीसी 434: रूप सिंह बनाम राम सिंह (2000) 3 एससीसी 708: कन्हैयालाल बनाम अनूप कुमार (2003) 1 एससीसी 430: चढ़त सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य (2004) 6 एससीसी 359: जोसेफ सेवेरेन और अन्य बनाम बेनी मैथ्यू और अन्य (2005) 7 एससीसी 667: शशिकुमार और अन्य बनाम कुन्नथ चेल्लप्पन नायर और अन्य (2005) 12 एससीसी 588; ज्वाला सिंह (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम जगत सिंह (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि जेटी (2006) 8 एससी 483 और सी.ए. सु एवं अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, सभी और अन्य (2006) 1 एससीसी 392 पर भरोसा किया गया।

2. धारा 100 की उपधारा (5) का प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही तैयार किया जा चुका हो और यह उच्च न्यायालय को कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील को रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से सुनने का अधिकार देता है। कानून के किसी भी अन्य ठोस प्रश्न पर अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कानून का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले से ही तैयार किया जाना चाहिए और फिर केवल कानून

का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले तैयार नहीं किया गया था, उसे दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा उठाया जा सकता है, यदि उसका विचार है कि इस मामले में ऐसे प्रश्नात्मक शामिल हैं।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5614/2006

(गुजरात उच्च न्यायालय स्थित अहमदाबाद के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 29.8.2002 के 1978 एस.ए. संख्या 491 में।)

अपीलार्थी की ओर से ए.रघुनाथ।

उत्तरदाताओं की ओर से -रामेश्वर प्रसाद गोयल।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया-

अनुमति प्रदान की गई।

इस अपील में चुनौती गुजरात उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को दी गई है, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में संहिता) की धारा 100 के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी, हालांकि विभिन्न प्रश्न थे अपील के समर्थन में उठाई गई, यह मुख्य रूप से उजागर किया गया था कि दूसरी अपील को कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार किए बिना अनुमति दी गई थी।

जब मामला बुलाया जाता है तो उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं होती है, हालांकि विद्वान वकील उपस्थित हुए थे।

संहिता की धारा 100 दूसरी अपील से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार है:

> "100 (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
>
> (2) इस धारा के तहत अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील की जा सकती है - एक पक्षीय पार्टी।
>
> (3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील का ज्ञापन अपील में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को सटीक रूप से बताता है।
>
> (4) जहां उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि किसी भी मामले में एक महत्वपूर्ण प्रश्न कानून शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।
>
> (5) अपील की सुनवाई इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर की जाएगी, और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है:

> बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी दर्ज किए जाने वाले कारणों से, कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील को सुनने की अदालत की शक्ति को समाप्त या कम करने वाला नहीं माना जाएगा। यदि यह संतुष्ट है कि मामले में ऐसी खोज शामिल है, तो इसके द्वारा तैयार किया जाएगा।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से यह पता चलता है कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किया गया है या प्रश्न पर दूसरी अपील सुनी गई थी, यदि कोई हो, तो तैयार किया गया। इसलिए, निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता।

ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल (2000) 1 एससीसी 434, में, यह न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

> "10. अब धारा 100 सीपीसी के तहत, 1976 के संशोधन के बाद, उच्च न्यायालय के लिए लॉ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना आवश्यक है और ऐसा किए बिना प्रथम अपील अदालत के फैसले को उलटने की अनुमति नहीं है।"

एक बार फिर रूप सिंह बनाम राम सिंह में (2000) 3 एससीसी 708, इसने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ी अपीलों तक ही सीमित है। उक्त निर्णय के पैरा 7 में लिखा है:

"7. यह दोहराया जाना चाहिए कि सीपीसी की धारा 100 के तहत क्षेत्राधिकार दूसरी अपील पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय केवल ऐसी अपीलों तक ही सीमित है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह धारा 100 सी सीपीसी के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय तथ्य के शुद्ध प्रश्नों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, मामले के निपटारे के समय, हाई कोर्ट ने दूसरी अपील स्वीकार करने के समय उसके द्वारा तैयार किए गए कानून के सवाल पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आक्षेपित फैसले में इसका कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, साक्ष्यों की सराहना करने के बाद तथ्यान्वेषी अदालतों ने माना कि प्रतिवादी ने इसमें प्रवेश किया था। बटाई के रूप में परिसर का कब्ज़ा, यानी एक किरायेदार के रूप में और उसका कब्ज़ा अनुमेय था और यह कब प्रतिकूल और शत्रुतापूर्ण हो गया, इसके बारे में कोई दलील या सबूत नहीं था। नीचे दी गई दो अदालतों द्वारा दर्ज किए गए ये निष्कर्ष सबूतों की उचित सराहना पर आधारित थे और रिकॉर्ड पर सामग्री और कोई विकृति नहीं थी। उन निष्कर्षों में अवैधता या अनियमितता। यदि प्रतिवादी को पट्टेदार के रूप में या बटाई समझौते के तहत वाद भूमि पर कब्ज़ा मिला है, तो उसे अनुमेय कब्जे से शत्रुतापूर्ण शत्रुता और पेज 1532 और वास्तविक

मालिक के ज्ञान के प्रतिकूल कब्ज़ा दिखाने के लिए ठोस और ठोस सबूत के माध्यम से स्थापित करना होगा। केवल लंबे समय तक कब्ज़ा रखने से अनुमेय कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़े में परिवर्तित नहीं हो जाता (ठाकुर किशन सिंह बनाम अरविंद कुमार)। (1994) 6 एससीसी 591। इसलिए उच्च न्यायालय को नीचे दी गई दोनों अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।"

कन्हैयालाल बनाम अनूप कुमार मामले में स्थिति दोहराई गई है। (2003) 1 एससीसी 430।

चदत सिंह बनाम बहादुर राम और अन्य में। (2004) 6 एससीसी 359, यह इस प्रकार देखा गया था:

"6. संहिता की धारा 100 के मद्देनजर अपील के ज्ञापन में धारा 100 की उप-धारा (3) के तहत आवश्यक अपील में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्न या प्रश्न स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे। जहां उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी मामले में कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न कानून शामिल है, यह उस प्रश्न को उप-धारा (4) के तहत तैयार करेगा और धारा 100 की उप-धारा (5) में बताए गए अनुसार तैयार किए गए प्रश्न पर दूसरी अपील सुनी जाएगी।"

जोसेफ सेवेरेन और अन्य में इस न्यायालय द्वारा स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। वी. बेनी मैथ्यू और अन्य। (2005) 7 एससीसी 667: शशिकुमार और अन्य बनाम कुन्नथ चेल्लप्पन नायर और अन्य। (2005) 12 एससीसी 588: ज्वाला सिंह (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम जगत सिंह (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि जेटी (2006) 8 एससी 483 और सी.ए. सुलेमान एवं अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। सभी और अन्य। (2006) 6 एससीसी 392।

धारा 100 की उप-धारा (5) का प्रावधान केवल तभी लागू होता है जब कानून का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न पहले ही तैयार किया जा चुका हो और यह उच्च न्यायालय को कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील को दर्ज किए जाने वाले कारणों से सुनने का अधिकार देता है। "कानून के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है" कि कानून का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पहले से ही तैयार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही कानून का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए जो पहले तैयार नहीं किया गया था, इसे उच्च न्यायालय द्वारा कारणों के साथ दर्ज किया जा सकता है, यदि उसका मानना है कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।

इन परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है, और मामले को कानून के अनुसार निपटान के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है।

अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है।

डी.जी.

अपील खारिज ।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।